भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2549
21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

हरित इस्पात विनिर्माण को अपनाना

2549. # डॉ. भीम सिंह :
डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में हरित इस्पात विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं ;

(ख) हरित इस्पात उत्पादन को अपनाने के इच्छुक इस्पात विनिर्माताओं के लिए कौन-कौन सी वित्तीय सहायता या वित्तपोषण तंत्र उपलब्ध हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए कोई विशिष्ट साझेदारी या सहयोग किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): देश में हरित इस्पात विनिर्माण को अपनाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता सहित उठाए गए विशिष्ट उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक प्रदान करने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और एक्शन प्लान" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की ओर हरित इस्पात और संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जारी.....2/-

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय को वित्त वर्ष 2029-30 तक 455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस्पात मंत्रालय ने इस मिशन के तहत कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए वर्टिकल शॉफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डीआरआई का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना प्रदान की है।

iv. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता करता है।

(ग) और (घ): इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई निम्न कार्बन इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेसर्स बीएचपी, जर्मनी से मेसर्स एसएमएस, यूनाइटेड किंगडम से मेसर्स प्राइमेटल टेक्नोलॉजीज, बेल्जियम से मेसर्स जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेड, मद्रास से मेसर्स राम चरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आईआईटी, बॉम्बे के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन (एनसीओई-सीसीयू) और ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

*****